

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।  
(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं०-89/2023-24

सरकार

-बनाम-

श्रवण कुमार

आ दे श

20/10/23

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक -2604/अप०शा० दिनांक -23.09.2023 के द्वारा वादिनी रेशमा रेखा मिंज पे०-स्व० फ्रांसिस मिंज सा०-बड़गढ़ थाना-भंडरिया जिला-गढ़वा वर्तमान अंचल अधिकारी डुमरी के टंकित आवेदन के आधार पर डुमरी थाना काण्ड सं०-23/2023 दिनांक-26.07.2023 धारा-379/411 भा०द०वि० 21 खान और खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम-1957, 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004, 13 झारखण्ड खनिज(अवैध खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम-2017 के तहत अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर बेचने के उद्देश्य से परिवहन करने के आरोप में जप्त ट्रैक्टर रजि० सं० -JH07K-9645 के मालिक श्रवण कुमार पे०-विजय साहु सा०-करमदोन, थाना-डुमरी, जिला-गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन में अंकित है कि अंचल अधिकारी डुमरी के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त जप्त ट्रैक्टर रजि० सं० -JH07K-9645 के मालिक श्रवण कुमार पे०-विजय साहु सा०-करमदोन, थाना-डुमरी, जिला-गुमला के विरुद्ध अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर बेचने के उद्देश्य से परिवहन करने के आरोप में अंकित किया गया है एवं इस कांड के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 (यथा संशोधित) के नियम-4 एवं 54 MMDR Act. 1957 के धारा-4 एवं 21 तथा Jharkhand Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules-2017 के नियम-7 एवं 13 के तहत मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ट्रैक्टर रजि० सं० -JH07K-9645 के विरुद्ध अवैध रूप से बालू का खनन कर बेचने के उद्देश्य से परिवहन करने के आरोप को सत्य पाया गया है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मामला माईन्स और मिनिरल एक्ट से संबंधित है। उत्तरवादी पर अवैध बालू परिवहन का आरोप है। उत्तरवादी पर लगाया गया आरोप झूठा है। उत्तरवादी को ग्राम-पंचायत सचिवालय मझगाँव डुमरी से आदेश प्राप्त हुआ था कि लाभुक स्व० जनमसाय भगत के आवास निर्माण के उपरान्त शेष बचे हुए भण्डारित बालू को उठाकर दूसरे लाभुक के आवास पर पहुंचा दिया। उत्तरवादी कही से चोरी कर बालू का परिवहन दूसरे स्थान पर नहीं कर रहा था। पंचायत सचिवालय के आदेश पर

बालू पहुंचा रहे थे। उसी बीच वाद दर्ज किया गया है। वाद अनुसंधान में चल रहा है, वाद सिविल न्यायालय में लंबित है। उत्तरवादी द्वारा पुलिस अधीक्षक गुमला एवं थाना प्रभारी डुमरी को सभी तथ्यों को लिखित आवेदन देकर अवगत कराया गया है। अधिहरण वाद का प्रक्रिया अंतिम विकल्प है, जब न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने के उपरान्त अधिहरण की कार्रवाई की जायगी। उत्तरवादी बिल्कुल निर्दोष है। अधिहरण वाद चलने योग्य नहीं है। उत्तरवादी के द्वारा अधिहरण वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:-

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing any mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being registered as a dealer."

(2) Rule 11 (V) के अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court.

(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi के मूल आवेदन सं0-360/2015 प्रतिवेदित तिथि 15.01.2021 में यह अभिकथन किया गया है कि "Another issue bearing on the enforcement mechanism is the action against the vehicles used in illegal sand mining. Seizure of such vehicles is required and release of seized vehicles lightly defeats the purpose of the coercive measures. Since the vehicles are in a way weapon of offence, the same cannot be dealt with in the manner disputed property is dealt with under section 451 Cr.PC. by releasing the same in favour of the ostensible owner by taking an entrustment /indemnity bond/sapurdginama. In Sujit Kumar Rana"

अंकनीय है कि इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं डाला में पंजीकरण संख्या नहीं रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नहीं होने के कारण उसको अवैध रूप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त बालू एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त बालू एवं ट्रैक्टर रजि0 सं0 -JH07K-9645 को राजसात करता हूँ।

आदेश की प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,  
गुमला

उपायुक्त,  
गुमला